



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]
No. 170]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2008/चैत्र 8, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2008/CHAITRA 8, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विधान)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2008

सा.का.नि. 250(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“सं. आ. 240

संविधान (राजस्व वितरण) सं. 11 आदेश, 2008

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बाहरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण)

सं. 11 आदेश, 2008 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित की राजस्व सहायता अनुदान के रूप में, भारत की संचित निधि पर भारत होंगी,—

(क) नीचे सारणी के संबंध (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुदानों में उक्त सारणी के संबंध (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां:—

सारणी

राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	31740.00
असम	10520.00
बिहार	48720.00
छत्तीसगढ़	12300.00

	(1)	(2)
गोवा		77.00
गुजरात		18620.00
हरियाणा		7760.00
हिमाचल प्रदेश		2940.00
कर्नाटक		8880.00
केरल		19700.00
मध्य प्रदेश		33260.00
महाराष्ट्र		39660.00
मणिपुर		211.60
नागालैण्ड		400.00
उड़ीसा		16060.00
पंजाब		3240.00
राजस्थान		12300.00
तमिलनाडु		8700.00
उत्तर प्रदेश		87840.00
उत्तराखण्ड		1620.00
पश्चिमी बंगाल		25420.00:

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बाहरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विद्युत उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोग के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार की जाएंगी ;

(ख) नीचे सारणी के संबंध (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों में उक्त सारणी के संबंध (2) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियां :—

सारणी	
राज्य	रुपए लाख में
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	3740.00
अरुणाचल प्रदेश	60.00
असम	1100.00
बिहार	2840.00
छत्तीसगढ़	880.00
गुजरात	8280.00
हरियाणा	1820.00
हिमाचल प्रदेश	160.00
कर्नाटक	3230.00
केरल	2980.00
मध्य प्रदेश	3610.00
महाराष्ट्र	7910.00
मणिपुर	90.00
नागालैण्ड	60.00
पंजाब	3420.00
राजस्थान	2200.00
तमिलनाडु	5720.00
उत्तर प्रदेश	15510.00
पश्चिमी बंगाल	7860.00:

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में शहरी स्थानीय निकायों को संदत्त की जाएंगी और ये राशियां राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त राशियों के अतिरिक्त होंगी :

परन्तु यह और कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट उसकी सिफारिशों के अनुसार तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों के उपयोग के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह भी कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए अनुपयोजित अनुदान अगले वर्ष के लिए अप्रीनीत किया जा सकेगा ;

(2) उप-पैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, राज्यों को अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतुकों में से प्रत्येक के अधीन संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल,

राष्ट्रपति ।”।

[फासं. 19(11)/2008-विधायी I]

के. डी. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2008

G.S.R. 250(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“C. O. 240

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 11 ORDER, 2008

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Twelfth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 11 Order, 2008.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2007, as grants-in-aid of the revenues to—

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards grants for Panchayati Raj Institutions, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	31740.00
Assam	10520.00
Bihar	48720.00
Chhattisgarh	12300.00
Goa	77.00
Gujarat	18620.00
Haryana	7760.00
Himachal Pradesh	2940.00
Karnataka	8880.00
Kerala	19700.00
Madhya Pradesh	33260.00
Maharashtra	39660.00
Manipur	211.60
Nagaland	400.00
Orissa	16060.00
Punjab	3240.00
Rajasthan	12300.00
Tamil Nadu	8700.00
Uttar Pradesh	87840.00
Uttarakhand	1620.00
West Bengal	25420.00:

Provided that the sums specified above shall be paid to the Panchayati Raj Institutions in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Panchayati Raj Institutions from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by the Panchayati Raj Institutions as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter 8 of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in this regard for utilisation of the grants;

(b) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the said Table, towards grants for Urban Local Bodies, namely :—

TABLE

State	Rupees in lakhs
(1)	(2)
Andhra Pradesh	3740.00
Arunachal Pradesh	60.00
Assam	1100.00
Bihar	2840.00
Chhattisgarh	880.00
Gujarat	8280.00
Haryana	1820.00
Himachal Pradesh	160.00
Karnataka	3230.00
Kerala	2980.00
Madhya Pradesh	3610.00
Maharashtra	7910.00

	(1)	(2)
Manipur		90.00
Nagaland		60.00
Punjab		3420.00
Rajasthan		2200.00
Tamil Nadu		5720.00
Uttar Pradesh		15510.00
West Bengal		7860.00

Provided that the sums specified above shall be paid to the Urban Local Bodies in the said financial year by a State Government and these sums shall be in addition to the sums flowing to the Urban Local Bodies from the State Government :

Provided further that the sums specified above shall be expended by the Urban Local Bodies as per the recommendations of the Twelfth Finance Commission contained in Chapter 8 of its report and in accordance with the guidelines issued by the Central Government to the State Governments in this regard for utilisation of the grants :

Provided also that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisions to clause (1) of article 275.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,
President.”

[F. No. 19(11)/2008-Leg. I]
K. D. SINGH, Secy.